UPSC-CSE 2027/28
DAILY
CURRENT AFFAIRS
ONE STOP SOLUTION
By Faiyaz Sir
The Indian EXPRESS
THE HINDU
pib
PRESS INFORMATION BUREAU
15
SEPTEMBER
COMPQETE COVERAGE
EXAM FOCUSED
ANALYSIS MADE EASY
STATIC + CURRENT INTEGRATION
STAY AHEAD
STAY PREPARED

Result Mitra
Big
Dreams
Big
Plans
आँखों में अरमान लिया है,
मंज़िल को अपना मान लिया है।
मुश्किल क्या और आसान क्या,
जब ठान लिया तो ठान लिया है।
Dr. Faiyaz Sir
UPSC
CURRENT AFFAIRS
POLITY
ECONOMY
HISTORY
GEOGRAPHY
Keep
Going

आज क्या पढ़ेंगे?

1. Data Center — S&T
2. UCC — Polity & Constitution
3. महत्वपूर्ण तथ्य →

Technology

भारत में डेटा सेंटरः डिजिटल युग का बुनियादी ढांचा

- डिजिटल युग में डेटा सेंटर modern infrastructure के मजबूत पिलर हैं।

1. डेटा सेंटर क्या होते हैं? (What are Data Centers?)

- डेटा सेंटर एक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई बड़ी भौतिक सुविधा (building) होती है, जहाँ हजारों कंप्यूटर सर्वर, डेटा स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क स्विच और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ रखा जाता है। इनका मुख्य काम दुनिया भर के डिजिटल डेटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना और सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करना है।

2. डेटा सेंटर क्यों जरूरी हैं? (Why are they Important?)

- **डिजिटल सेवाओं का आधार:** बैंकिंग (UPI/NetBanking), ई-गवर्नेंस (Aadhaar/DigiLocker), ऑनलाइन स्ट्रीमिंग (YouTube/Netflix), और सोशल मीडिया बिना डेटा सेंटर के काम नहीं कर सकते।
- **AI और फ्यूचर टेक:** AI (Artificial Intelligence), क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G टेक्नोलॉजी को भारी कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है, जो डेटा सेंटर ही प्रदान करते हैं।
- **डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty):** भारतीयों का डेटा भारत की सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित और प्रोसेस हो सके, इसके लिए स्वदेशी डेटा सेंटर्स का होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है।

3. डेटा सेंटर कैसे काम करते हैं? (How do they Work?)

- **डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज:** जब आप अपने फोन या लैपटॉप पर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं (जैसे गूगल सर्च या ऑनलाइन पेमेंट), तो यह नेटवर्क के जरिए सर्वर तक पहुँचता है, जहाँ डेटा प्रोसेस होकर सेकेंड के छोटे हिस्से में वापस आपके डिवाइस तक परिणाम भेजता है।
- **24/7 पावर और रिडंडेंसी:** ये सेंटर्स बिना रुके चलते हैं। इनके लिए लगातार बिजली की जरूरत होती है, जिसके लिए ग्रिड पावर के साथ बड़े बैकअप डीजल जनरेटर और UPS (Uninterruptible Power Supply) लगाए जाते हैं।
- **कूलिंग सिस्टम (Cooling):** हजारों सर्वर लगातार चलने से बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए एडवांस्ड कूलिंग (Liquid Cooling, Direct-to-Chip, Immersion Cooling) का उपयोग किया जाता है।
- **साइबर और फिजिकल सिक्योरिटी:** बायोमेट्रिक एक्सेस control, CCTV सुरक्षा और फायरवॉल जैसी तकनीकों से इन्हें साइबर हमलों और भौतिक खतरों से बचाया जाता है।

4. भारत सरकार डेटा सेंटर्स के लिए क्या कर रही है? (Government Initiatives)

- **इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस (Infrastructure Status):** केंद्र सरकार ने डेटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है, जिससे कंपनियों के लिए सस्ता लोन पाना आसान हो गया है।
- **ग्रीन एनर्जी और नीतियाँ:** स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स' और टिकाऊ cooling मानकों को लागू किया जा रहा है।
- **AI मिशन और वित्तीय प्रोत्साहन:** AI आधारित हाई-डेंसिटी डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर बिजली और टैक्स में छूट (Tax Holiday) जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

5. भारत में डेटा सेंटर्स कहाँ-कहाँ स्थापित हैं? (Major Hubs in India)

- भारत की कुल स्थापित क्षमता (installed capacity) हाल ही में लगभग 1,575 MW पहुँच चुकी है। देश के प्रमुख डेटा सेंटर hubs

शहर / क्षेत्र	कुल हिस्सेदारी / खासियत	प्रमुख इलाके व बातें
मुंबई और नवी मुंबई	~50%+ (भारत का सबसे बड़ा हब)	ऐरोली, ठाणे-बेलापुर कॉरिडोर, पनवेल (समुद्री सबमरीन केबल्स से सीधा जुड़ाव)
चेन्नई	दूसरा सबसे बड़ा हब	सिरुसेरी और अंबरतूर (सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशंस का बड़ा केंद्र)
दिल्ली-NCR (नोएडा)	उत्तर भारत का प्रमुख हब	सेक्टर-132 और ग्रे. नोएडा (Yotta D1, AdaniConneX आदि के हाइपरस्केल डेटा सेंटर)
बेंगलुरु	टेक और AI वर्कलोड	व्हाइटफील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी (Nxtra, NTT, Iron Mountain)
हैदराबाद	तेजी से उभरता हब	गाचीबोवली और HITEC सिटी (AWS और Microsoft के बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स)
अन्य उभरते केंद्र	नए निवेश गंतव्य	पुणे, कोलकाता, गुजरात (GIFT City), और आंध्र प्रदेश

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice Questions)

प्रश्न 1. डेटा सेंटर (Data Centers) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत सरकार ने डेटा सेंटर्स को बुनियादी ढांचे (Infrastructure Status) का दर्जा दिया है, जिससे दीर्घकालिक और कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है।
2. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स (Green Energy Open Access Rules) का उद्देश्य डेटा सेंटर्स जैसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) तक पहुँच को आसान बनाना है।
3. सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन (Submarine Cable Landing Stations) की मौजूदगी के कारण मुंबई और चेन्नई भारत में डेटा सेंटर हब के रूप में उभरे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Questions)

- **प्रश्न 1 (GS Paper 3 - अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी):**
- "डेटा सेंटर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अदृश्य स्तंभ (Invisible Pillars) हैं।" इस कथन के आलोक में, भारत में डेटा सेंटर उद्योग के महत्व, इसके तीव्र विकास के कारकों तथा इसके समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। *(250 शब्द / 15 अंक)*

AFTER SHAH SAYS UCC IN NDA STATES BY '29

NDA allies TDP and Sena back Uniform Civil Code, JD(U) says not in Bihar

Union Home Minister Amit Shah with Maharashtra CM Devendra Fadnavis on Ganesh Chaturthi in Mumbai, Monday. PTI

Not a hidden agenda for us, says Bengal BJP chief

Liz Mathew & Jatin Anand
New Delhi, September 14

A DAY after Union Home Minister Amit Shah announced that a Uniform Civil Code (UCC) would be implemented in all 21 NDA-ruled states before the next Lok Sabha polls in 2029, most alliance partners came out in support of the move. A few other NDA allies, however, adopted a cautious approach while the JD(U) made it clear that it would not allow any such move in Bihar.

The TDP, on which the BJP-led NDA depends for a majority in Parliament and which has a significant Muslim vote bank in Andhra Pradesh, expressed support for the move, as did the Shiv Sena and the Hindustani Awam Morcha (Secular).

"We will be supporting it," Lavu Krishna Devarayalu, leader of TDP in the Lok Sabha, told *The Indian Express*. "As of now, there is no discussion. But whenever we find the need for it, we will be looking into it. We will definitely involve various stakeholders before we adopt it," Krishna said.

The TDP and JD(U), which also has a sizeable Muslim vote bank in Bihar, had earlier opposed any legislation without adequate consultation, but the TDP appears to have since softened its stand on the issue. "It (UCC) is very much needed in a country like India, which has different religions and cultures," said a TDP leader.

Before the TDP joined the

»CONTINUED ON PAGE 2

- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने की अवधारणा है। वर्तमान में भारत में विभिन्न धर्मों के अपने 'पर्सनल लॉ' (जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि) हैं।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

- **अनुच्छेद 44 (Article 44):** यह राज्य नीति के निर्देशक तत्वों (DPSP - Part IV) के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि "राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"
- **गैर-न्यायिक (Non-Justiciable):** DPSP होने के कारण इसे अदालत के माध्यम से जबरन लागू नहीं कराया जा सकता, यह सरकार की नीतिगत मंशा पर निर्भर करता है।
- **अनुच्छेद 25-28 से टकराव:** UCC का मुख्य संवैधानिक बहस अनुच्छेद 25-28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है।

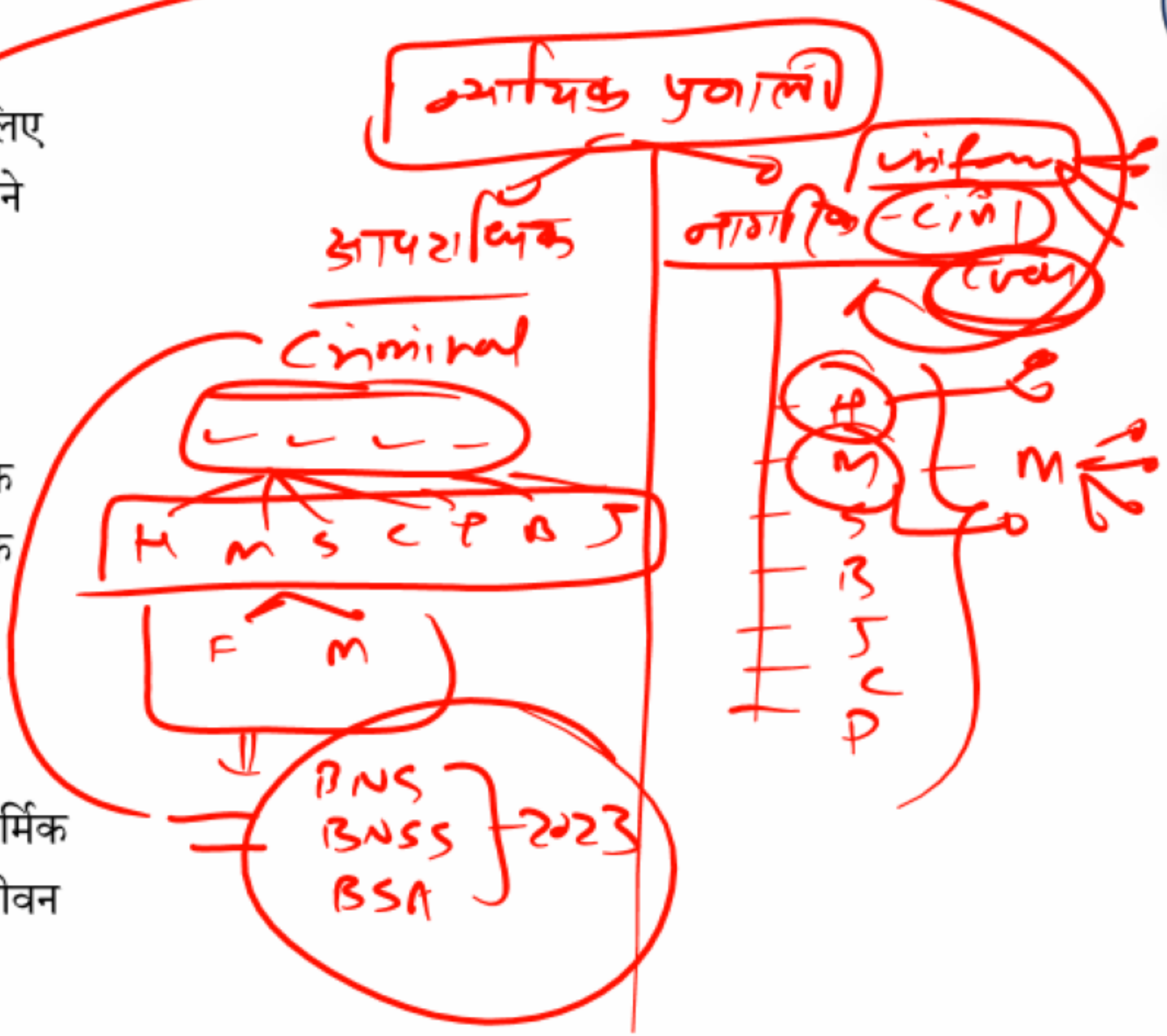

UCC की आवश्यकता क्यों है? (Why is UCC Needed?)

- **लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण:** वर्तमान पर्सनल लॉ में कई जगह महिलाओं के अधिकार (जैसे तलाक, रखरखाव, और उत्तराधिकार) असमान हैं। UCC से सभी महिलाओं को समान कानूनी संरक्षण मिलेगा।
- **संवैधानिक समानता (Equality under Law):** एक ही अपराध या नागरिक मामले में धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनों का होना अनुच्छेद 14 की मूल भावना के विपरीत माना जाता है।
- **राष्ट्रीय एकीकरण (National Integration):** समान कानून से धार्मिक और सामुदायिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय पहचान और नागरिक एकता को बढ़ावा मिलता है।
- **कानूनी सरलीकरण:** दर्जनों जटिल और विरोधाभासी पर्सनल कानूनों की जगह एक पारदर्शी और सरल सिविल कोड से न्याय व्यवस्था अधिक सुलभ होगी।

किन-किन राज्यों में UCC लागू/पारित हुआ है? (States Status)

- **गोवा (Goa):**
  - गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ **1867 का पुर्तगाली नागरिक कोड (Portuguese Civil Code)** पहले से लागू है। इसे स्वतंत्रता के बाद भी बनाए रखा गया।
- **उत्तराखंड (Uttarakhand):**
  - स्वतंत्रता के बाद विधानसभा से पारित कर UCC कानून लागू करने वाला **उत्तराखंड देश का पहला राज्य** बना। यहाँ 2024 में विधेयक पारित हुआ और 2025 में इसके नियम लागू हुए।
- **अन्य राज्य (हालिया स्थिति):**
  - **गुजरात, असम, और मध्य प्रदेश** की विधानसभाओं ने भी UCC विधेयक पारित कर दिए हैं (राष्ट्रपति की सहमति और अधिसूचना की प्रक्रिया के तहत)।
  - राजस्थान, महाराष्ट्र, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है।

UCC की सीमाएँ और चुनौतियाँ (Limitations & Concerns)

- **सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता:** भारत विविध रीति-रिवाजों का देश है। आलोचकों का मानना है कि एक समान कानून थपने से अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता (Article 25) प्रभावित हो सकती है।
- **जनजातीय (Tribal) छूट और अपवाद:** अधिकांश UCC मसौदों (जैसे उत्तराखंड UCC) में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को उनकी विशिष्ट परंपराओं की रक्षा के लिए दायरे से बाहर रखा गया है। इससे "पूर्ण समानता" के विचार पर सीमा लग जाती है।
- **निजता का अधिकार (Right to Privacy):** उत्तराखंड UCC में 'लाइव-इन रिलेशनशिप' (Live-in Relationships) का अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर जेल या जुर्माने का प्रावधान है। आलोचकों का तर्क है कि यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का उल्लंघन है।
- **संघवाद की चुनौती (Federalism):** संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List - Item 5) में होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अलग-अलग राज्यों द्वारा अपने स्तर पर UCC लाने से देश भर में कानूनों की असमानता (Disparity) बनी रह सकती है, जो UCC के मूल उद्देश्य को प्रभावित करती है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice Questions)

प्रश्न 1. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत UCC को राज्य नीति के निर्देशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत शामिल किया गया है।
2. भारत में 'विवाह और तलाक' (Marriage and Divorce) संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) के अंतर्गत आते हैं।
3. अनुच्छेद 44 के प्रावधानों को अदालतों द्वारा लागू (Enforceable by Courts) कराया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Questions)

- "समान नागरिक संहिता (UCC) का कार्यान्वयन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) के मध्य संतुलन का परीक्षण करता है।" चर्चा कीजिए। *(250 शब्द / 15 अंक)*

महत्वपूर्ण तथ्य

DEBATE OVER ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Beijing hits back at Anthropic CEO's call to curb China's AI development

Associated Press
Beijing, September 14

CHINA'S MINISTRY of Foreign Affairs Monday hit back at a call from head of Anthropic for the US to curb China's artificial intelligence capabilities, which he issued as he argued for a global slowdown on AI development.

US President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping are expected to discuss AI governance, among other topics, at a meeting planned on Sept. 24.

Anthropic CEO Dario Amodei in a lengthy essay published on Saturday warned that a "Chinese lead in AI would pose grave danger for the United States and the world." He called for continuing restrictions on sales of cutting-edge AI chips and chipmaking equipment to China in order to keep the US's AI edge.

China's Ministry of Foreign Affairs responded to a question about Amodei's essay by saying that all parties should work together on AI.

"Fearmongering, confrontation and vicious competition will only disrupt the process of global AI governance which serves no one's interest," spokesperson Guo Jiakun said at a press conference Monday.

On Sunday, President Donald Trump downplayed calls for his administration to step in to slow down AI development, saying that the US was leading China on AI and that "whoever wins AI, wins."

Amodei predicted a swarm of AI "agents" could be able to take over the internet in six to 12 months unless researchers agree to slow down. He said "global pacing will require cooperation with China, the autocratic country with by far the most advanced AI capabilities."

Donald Trump is expected to discuss topics including AI governance with Chinese leader Xi Jinping meeting planned for late September.

Trump: There is a 'sick conspiracy' against AI firms

Washington: President Donald Trump said Monday that the US already has guardrails in place to regulate and prosecute AI companies.

"The only control or 'guardrails' that AI needs is a STRONG AND SMART (High IQ!) PRESIDENT, and the USA has that, in spades!" Trump wrote on Truth Social, adding that China would benefit from the doubt being cast on AI development.

"We already have tremendous CRIMINAL and REGULATORY power over these companies! There is a SICK conspiracy going on against AI and Data Centres, and the only one that is happy about it is China," he added. REUTERS

YouTube Homework

- Mythos

महत्वपूर्ण तथ्य

- एंथ्रोपिक (Anthropic) के सीईओ डेरियो अमोदेई (Dario Amodei) ने "वी मस्ट पेस द फ्रंटियर" (**We Must Pace the Frontier**) नाम से एक विस्तृत ओपन लेटर/निबंध प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने AI के बेकाबू होते विकास की गति को धीमा करने और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है।
- लेटर की मुख्य बातें और उस पर दुनिया भर से आई प्रतिक्रियाएँ:

1. डेरियो अमोदेई के लेटर में क्या कहा गया है?

- **AI विकास की तेज गति पर चिंता:** अमोदेई ने चेतावनी दी कि AI का विकास इंसान की समझ और नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। AI अब खुद अगले जनरेशन की AI बनाने में मदद कर रहा है (रिफरेंस: "Recursive Self-Improvement")।
- **गंभीर जोखिम:** अगर इसे अनियंत्रित छोड़ा गया, तो साइबर हमलों, जैविक आतंकवाद (bioterrorism), और पूरी इंटरनेट व्यवस्था पर कब्जा करने जैसे गंभीर वैश्विक खतरे पैदा हो सकते हैं।

3-स्टेप सेफ्टी प्लान (Three-Step Framework):

- **थर्ड-पार्टी इवैल्यूएटर्स (Embedded Auditors):** AI लैब्स को बाहरी और स्वतंत्र सुरक्षा जांचकर्ताओं को कंपनी के भीतर काम करने की अनुमति देनी चाहिए, जो मॉडल की ट्रेनिंग और सुरक्षा पर लगातार नज़र रखें।
- **लोकतांत्रिक देशों के बीच समन्वय:** लोकतांत्रिक राष्ट्रों की AI कंपनियों को एक मानक सुरक्षा नियम बनाना चाहिए ताकि गति के चक्कर में सुरक्षा से समझौता न हो।
- **वैश्विक सहयोग (Global Cooperation):** अमेरिका और सहयोगी देशों को चीन जैसे देशों के साथ भी AI सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बनाना चाहिए।
- **विकास रोकने की माँग नहीं:** उन्होंने साफ किया कि वे AI रिसर्च पर पूरी तरह से रोक (Pause) लगाने की माँग नहीं कर रहे हैं, बल्कि गति को नियंत्रित (Pacing) करके सुरक्षा ऑडिट के लिए समय निकालने की बात कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

2. इस लेटर पर क्या Response (प्रतिक्रियाएँ) आई हैं?

- इस पत्र के सामने आते ही टेक जगत और नीति-निर्माताओं में तीखी बहस छिड़ गई:
- **समर्थन (Industry Support):**
- **सैम ऑल्टमैन (OpenAI CEO):** उन्होंने अमोदेई के सुझाव का खुलकर समर्थन किया और कहा कि OpenAI भी अपनी लैब्स में स्वतंत्र थर्ड-पार्टी इवैल्यूएटर्स को शामिल करने के इस मॉडल को अपनाएगा।
- **इलोन मस्क (xAI/Tesla):** मस्क ने सोशल मीडिया पर अमोदेई के रुख का समर्थन करते हुए लिखा— *"Dario is right"* (डेरियो सही कह रहे हैं)।
- **आलोचना और संशय (Critics & Skepticism):**
- **डेविड सैक्स (Billionaire Tech Investor):** उन्होंने अमोदेई और सैम ऑल्टमैन दोनों को आड़े हाथों लेते हुए इसे "थिएटर/दिखावा" बताया। सैक्स ने कहा कि अगर उन्हें वाकई डर लग रहा है, तो वे सरकारी नियम बनने का इंतजार करने के बजाय खुद अपने मॉडल लॉन्च करना क्यों नहीं बंद कर देते? उन्होंने आरोप लगाया कि यह सुरक्षा का बहाना बनाकर नए कॉम्पिटिटर्स को रोकने (Regulatory Capture) की रणनीति है।
- **सरकारी व राजनीतिक प्रतिक्रिया (US Politicians):**
    - अमेरिकी प्रतिनिधियों (जैसे Rep. Ted Lieu) ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन यह सवाल भी उठाया कि क्या कंपनियां आपातस्थिति में अपने AI मॉडल और एजेंट्स को तुरंत बंद (Shut Down) करने की लिखित गारंटी दे सकती हैं?

महत्वपूर्ण तथ्य

U.S. FEDERAL RESERVE EXPECTED TO INCREASE INTEREST RATES THIS WEEK

Key inflation numbers rise in August, all eyes on RBI's interest rate decision next month

Inflation rates ticking up

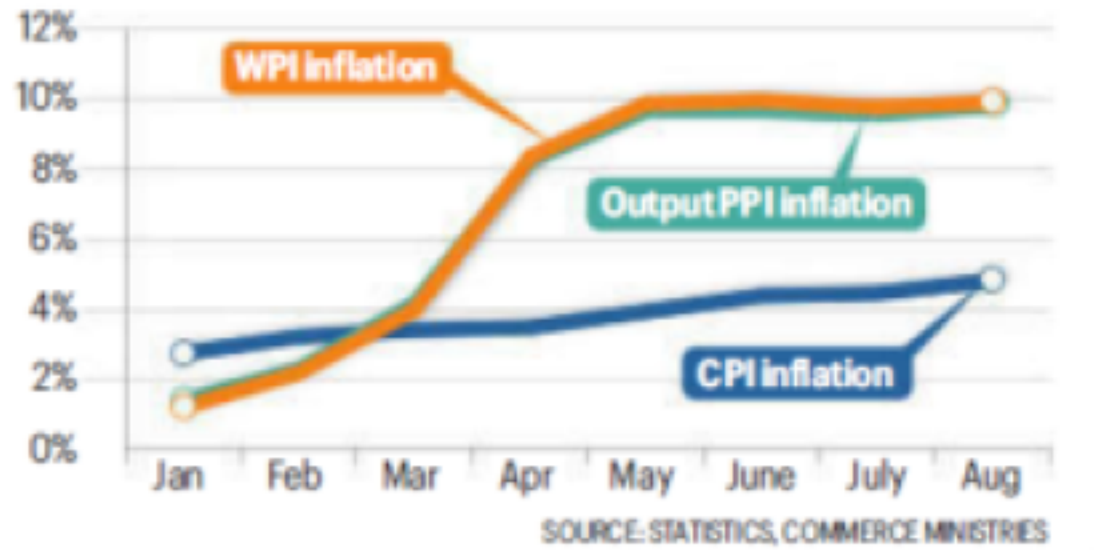

SOURCE: STATISTICS, COMMERCE MINISTRIES

Siddharth Upasani
New Delhi, September 14

A RANGE of indicators measuring prices rose in August, with the main gauge of household inflation rising to 4.82% from 4.45% in July — the highest in at least eight months — government data showed on Monday, bringing the focus on the October 5-7 meeting of the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC), which could see the first interest rate hike in three-and-a-half years.

While food inflation as measured by the Consumer Price Index (CPI) rose from 5.52% in July to 5.95% in August, upward pressure in prices was clearly visible for several items such as sugar and onion.

The CPI for sugar surged by 19% in August from July, and 24% as compared to August 2025. Prices have jumped due

»CONTINUED ON PAGE 2

EXPRESS special

Pressure on food prices: El Nino effect, geopolitical tensions

Dip in fertiliser sales warning signal

Harish Damodaran
New Delhi, September 14

THIS YEAR'S southwest monsoon has been rather erratic.

June, the opening month of the season, usually witnesses an average of three low-pressure systems (LPS) that cover a 24-hour period of about 11 days. This time, not a single LPS — which brings rain as warm, moist air near the ground rises into the atmosphere, where it cools and condenses into clouds — was formed. Rainfall over India as a whole was, then, 38%

»CONTINUED ON PAGE 2

FAO food price index

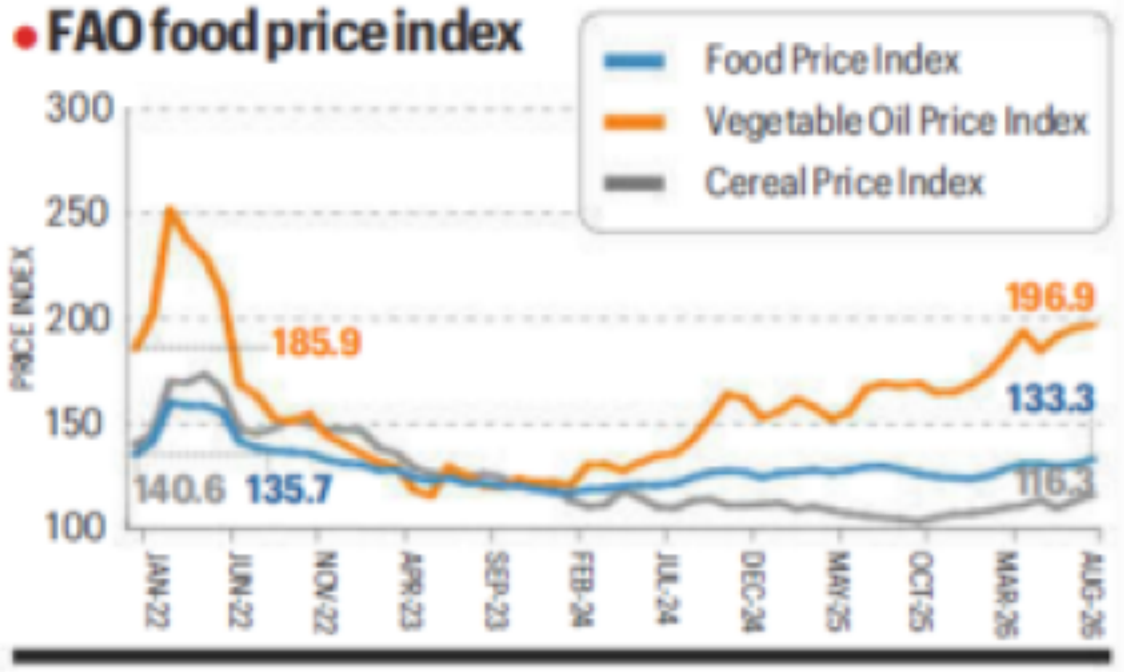

SOURCE: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

YouTube Homework

- Monetary Policy
- WPI
- CPI
- PPI
- IIP
- ISP
- Index of Core Industries

महत्वपूर्ण तथ्य

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी **अगस्त 2026** के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**CPI**) और थोक मूल्य सूचकांक (**WPI**) के आंकड़े:

1. CPI डेटा (Retail Inflation)

- रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि है।
- **हेडलाइन CPI:**
  - **अगस्त 2026: 4.82%** (जुलाई 2026 के **4.45%** से बढ़कर)।
  - **ग्रामीण महंगाई:** 5.23% (जुलाई में 4.84%)।
  - **शहरी महंगाई:** 4.31% (जुलाई में 3.96%)।
- **खाद्य महंगाई (CFPI):** बढ़कर **5.95%** हुई (जुलाई में 5.52% थी)।
- **किन वस्तुओं के दाम बढ़े/घटे?**
  - **तेजी:** प्याज (+48.27%), लहसुन (+43.60%), अदरक (+73.82%), चांदी के आभूषण (+107.11%), और सोने/हीरे के आभूषण (+35.53%) में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई।
  - **राहत:** टमाटर (-31.09%) और आलू (-13.14%) के दामों में गिरावट रही।
- **राज्य स्तर पर:** तेलंगाना में सबसे अधिक 6.27% रिटेल महंगाई दर्ज की गई, जबकि दिल्ली में सबसे कम (2.61%) रही।

2. WPI डेटा (थोक/Wholesale Inflation)

- थोक दरों के सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है:
- **हेडलाइन WPI:**
  - **अगस्त 2026: 9.92%** (जुलाई 2026 के **9.78%** से बढ़कर)।
- **प्रमुख घटकों (Major Groups) का रुझान:**
  - **ईंधन एवं बिजली (Fuel & Power):** 22.93% (जुलाई के 20.05% से बढ़कर)।
  - **निर्मित उत्पाद (Manufactured Products):** 8.37% (जुलाई में 8.29%)।
  - **प्राथमिक वस्तुएं (Primary Articles):** 7.76% (जुलाई में 8.52% से थोड़ी गिरावट)।
  - **WPI खाद्य सूचकांक (Food Index):** 7.05% (जुलाई के 6.65% से बढ़कर)।

महत्वपूर्ण तथ्य

EXEMPTION FOR RUPAY DEBIT CARD TOO

Govt: No bank charge on UPI payment up to Rs 2,000

In 2025-26, only 4% of person-to-merchant UPI payments were for over Rs 2,000

Siddharth Upasani
New Delhi, September 14

THE MINISTRY of Finance on Monday notified that banks and system providers cannot levy charges on UPI transactions of up to Rs 2,000 and RuPay debit card payments, paving the way for a fee to be levied on higher-value person-to-merchant transactions.

The ministry did not specify the charges for transactions above the specified amount. Whether a Merchant Discount Rate (MDR) fee will be imposed on higher-value person-to-merchant UPI transactions will be decided by the UPI and Services Steering Committee. Headed by the National Payments Corporation of India (NPCI), the committee has 22 members including banks, third-party application providers like PhonePe and Google Pay, Payments Council of India and Indian Banks' Association.

Payments industry officials have said earlier that an MDR of around 0.4-0.5% may be set for UPI payments to large merchants. This would help in meeting the industry's annual cost of about Rs 20,700 crore.

"No bank or system provider shall impose, whether directly or indirectly, any charge upon a person making or receiving a payment by using the electronic modes of payment specified in paragraph above," the government notification said on Monday, referring to a paragraph in which it specified RuPay debit cards and UPI transactions of up to Rs 2,000.

While only 4% of person-to-merchant UPI payments in 2025-26 were for more than Rs 2,000, these transactions accounted for about two-thirds of the total person-to-merchant UPI payments by value. More than 24,000 crore UPI transactions worth Rs 314 lakh crore were made in the year.

The notification comes after the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 — passed by Parliament last month — amended Section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, to remove exemption from bank charges for electronic payments under Section 269SU of the Income Tax Act, 1961.

»CONTINUED ON PAGE 2

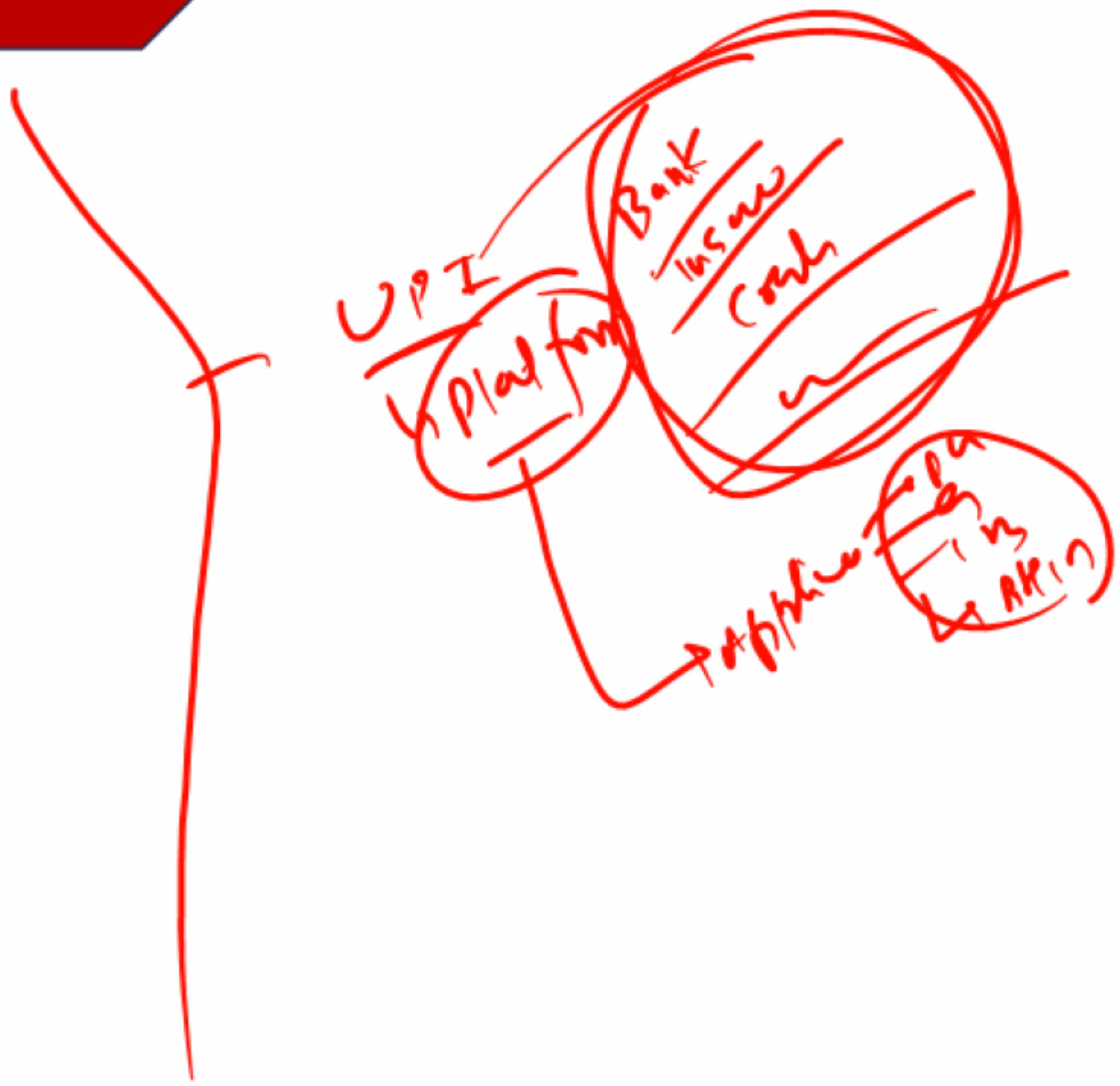

महत्वपूर्ण तथ्य

NPCI, UPI, इसकी वैश्विक पहुँच, MDR और इससे संबंधित हालिया चर्चा

1. NPCI और UPI क्या हैं?

NPCI (National Payments Corporation of India):

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों (Retail Payments and Settlement Systems) को संचालित करने वाला एक छत्र संगठन (Umbrella Organisation) है। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा 2008 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत स्थापित किया गया था। एनपीसीआई ही भारत में **RuPay, IMPS, NETC FASTag, AePS** और **UPI** जैसी प्रणालियों का प्रबंधन करता है।

UPI (Unified Payments Interface):

- यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक वास्तविक समय (Real-Time) भुगतान प्रणाली है, जो दो बैंक खातों के बीच मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुरंत धन हस्तांतरित करने की सुविधा देती है। इसे NPCI ने 2016 में लॉन्च किया था। यह बैंक खाते विवरण दर्ज किए बिना केवल UPI ID (VPA) या QR कोड के जरिए चौबीसों घंटे (24/7) सुरक्षित भुगतान की सुविधा देता है।

2. दुनिया में UPI कहाँ-कहाँ स्वीकार्य है? (Global Presence)

- NPCI की अंतरराष्ट्रीय शाखा **NIPL (NPCI International Payments Limited)** के माध्यम से भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहा है। वर्तमान में UPI या RuPay कार्ड निम्नलिखित प्रमुख देशों में स्वीकार किए जाते हैं:
- **सिंगापुर:** भारत के UPI और सिंगापुर के **PayNow** को आपस में जोड़ा गया है, जिससे दोनों देशों के निवासी सीधे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।
- **संयुक्त अरब अमीरात (UAE):** Mashreq Bank और NeoPay टर्मिनलों पर UPI QR कोड के जरिए भुगतान संभव है।
- **फ्रांस:** पेरिस में प्रसिद्ध एफिल टॉवर (Eiffel Tower) पर टिकट बुकिंग के लिए और कुछ चुनिंदा मर्चेंट्स पर UPI स्वीकार किया जाता है।
- **मॉरीशस और श्रीलंका:** इन देशों में भारतीय पर्यटक UPI QR के जरिए मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हैं।
- **नेपाल और भूटान:** इन पड़ोसी देशों में UPI आधारित भुगतान प्रणाली बड़े पैमाने पर क्रियान्वित की गई है।
- **ओमान और कतर:** इन देशों के सेंट्रल बैंकों और पेमेंट गेटवे के साथ समझौते के तहत भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के लिए UPI सेवाएं चालू की गई हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. MDR (Merchant Discount Rate) क्या है?

- **MDR** वह शुल्क या कमीशन होता है जो एक व्यापारी (Merchant) अपने ग्राहकों से डिजिटल भुगतान (जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वॉलेट) स्वीकार करने के बदले में बैंक और पेमेंट गेटवे कंपनियों को देता है।
- **उदाहरण:** यदि किसी मर्चेंट पर MDR **1%** है और आप वहाँ ₹1,000 का सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, तो व्यापारी को ₹990 मिलेंगे और ₹10 बैंक, कार्ड नेटवर्क (Visa/Mastercard) और पेमेंट गेटवे के बीच बट जाएँगे।

4. MDR पर हालिया चर्चा और विवाद (Recent Discussion on MDR)

- भारत में MDR को लेकर मुख्य बहस **UPI** और **RuPay डेबिट कार्ड** पर लागू शून्य-एमडीआर (Zero-MDR Policy) को लेकर हो रही है:
- **Zero-MDR नीति का इतिहास:** जनवरी 2020 में भारत सरकार ने डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर MDR शून्य (0%) कर दिया था। यानी व्यापारियों से UPI भुगतान लेने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता।

फिनटेक कंपनियों और बैंकों की चिंता:

- **राजस्व का नुकसान:** बैंक, पेमेंट ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) और पेमेंट एग्रीगेटर का तर्क है कि बुनियादी ढांचे, सर्वर रखरखाव, सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने में भारी लागत आती है। 0% MDR के कारण उन्हें इन सेवाओं को जारी रखने के लिए कोई प्रत्यक्ष आय नहीं हो रही है।
- **इनोवेशन पर प्रभाव:** पेमेंट इंडस्ट्री की संस्थाओं (जैसे Payments Council of India - PCI) ने सरकार से मांग की है कि बड़े मर्चेंट्स पर बहुत मामूली MDR फिर से लागू किया जाए या फिर सरकार हर साल बजटीय सहायता से सब्सिडी बढ़ाकर प्रदान करे।

हालिया विकास एवं सरकारी रुख:

- **क्रेडिट कार्ड ऑन UPI पर MDR:** NPCI ने **RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने** पर MDR लागू किया है। हालाँकि, ₹2,000 से कम के छोटे मर्चेंट लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन उससे अधिक पर सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह MDR लागू होता है।
- **सरकारी सब्सिडी:** सरकार हर साल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बजट में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, लेकिन फिनटेक क्षेत्र का मानना है कि यह लंबी अवधि के लिए एक स्थायी बिजनेस मॉडल नहीं है।
- **छोटे व्यापारियों की सुरक्षा:** सरकार और RBI इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आम जनता और छोटे दुकानदारों (Small Merchants) पर बिना कोई वित्तीय बोझ डाले, पेमेंट इकोसिस्टम को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए।

महत्वपूर्ण तथ्य

India, Vietnam agree to deepen defence ties, co-produce military equipment

Shubhajit Roy
New Delhi, September 14

External Affairs Minister S Jaishankar with Vietnamese counterpart Le Hoai Trung in New Delhi. PTI

WITH AN eye on China's assertive behaviour in the Indo-Pacific region, India and Vietnam agreed to deepen defence and security cooperation, including thorough co-production of Indian defence equipment, after External Affairs Minister S Jaishankar met visiting Foreign Minister of Vietnam Le Hoai Trung on Monday.

Jaishankar, who co-chaired the 19th India-Vietnam Joint Commission Meeting (JCM) on trade, economic, scientific and technological cooperation with the Vietnamese minister, said: "Vietnam for us is a key partner in India's Act East Policy, in our Vision MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) in outlook of the Indo-Pacific. Vietnam is equally an important partner in the framework of our Comprehensive Strategic Partnership with ASEAN (Association of South-east Asian Nations)."

Defence and security cooperation is among the central pillars of the enhanced Comprehensive Strategic Partnership between India and Vietnam.

Bilateral defence engagement has also diversified to wider military-to-military dialogue and capacity building and training among all arms of the forces. In July 2023, India gifted an indigenously built missile corvette INS Kirpan to Vietnam. Earlier, 12 high-speed guard boats, built by Indian manufacturer Larsen & Toubro under a bilateral line of credit of USD 100 million, were handed over to Vietnam in June 2022. Two more Lines of Credit of USD 120 million and USD 180 million have been signed between the Exim Bank of India and the Finance Ministry of Vietnam in July 2024, and are being undertaken currently.

According to the official statement on the bilateral talks: "They (India, Vietnam) identified the way forward on deepening ongoing defence and security collaboration, including through co-production of Indian defence items; expanding trade, investments and mutually beneficial supply chains; market access for Indian marine and agricultural products and pharmaceuticals; financial, port and air connectivity; opportunities in nuclear energy and space sector; heritage conservation; cooperation in standards for seafarers; capacity building and people-to-people ties."

The two ministers noted that discussions between the general secretary of the Communist Party of Vietnam and the President of Vietnam, To Lam, and PM Modi, including during the former's State Visit to India in May 2026, provided "renewed impetus to the bilateral relationship".

Jaishankar said, "I am very glad to note that our bilateral ties have progressed significantly since the previous meeting of the Joint Commission, which was held three years ago. We have had two important State Visits from Vietnam in the meanwhile, most notably, the State Visit of General Secretary and President To Lam to India. And during this visit, our leaders elevated their relationship to an Enhanced Comprehensive Strategic Partnership. It is noteworthy that Vietnam is the first country in the region with which we have bilateral ties at that level."

It said that in a "productive and outcome-oriented discussion", the two ministers reviewed the full spectrum of bilateral relations under the India-Vietnam Enhanced Comprehensive Strategic Partnership. The MEA said it appreciated the growing popularity of Yoga in Vietnam. They also agreed to observe next year as the Year of India-Vietnam Friendship to mark 55 years of diplomatic ties. They welcomed Vietnam's engagement under India's Indo-Pacific Oceans Initiatives (IPOI), it said.

"The two sides exchanged views on regional and global developments of mutual interest and reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral fora," the MEA said.

The ministers expressed satisfaction at upward and growing trajectory of bilateral relations and agreed to convene the next Joint Commission Meeting on a mutually convenient date.

According to the MEA, "Vietnam is a key pillar of India's Act East Policy. Rooted in deep civilisational linkages, the India-Vietnam Enhanced Comprehensive Strategic Partnership continues to grow from strength to strength across established and new areas of cooperation."

YouTube Homework

- SAGAR
- MAHASAGAR

महत्वपूर्ण तथ्य

- **रक्षा और सैन्य उपकरणों का सह-उत्पादन (Co-production):** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारत और वियतनाम भारतीय रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन (co-production) और रक्षा-सुरक्षा संबंधों को गहरा करने पर सहमत हुए हैं।
- **उच्च स्तरीय बैठक:** भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वियतनाम के विदेश मंत्री ले होआई ट्रुंग (Le Hoai Trung) के बीच नई दिल्ली में 19वीं भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग बैठक (JCM) आयोजित हुई।
- **कूटनीतिक संबंध:** जयशंकर ने वियतनाम को भारत की **Act East Policy** और **Vision MAHASAGAR** का एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार बताया।
- **पिछला रक्षा सहयोग:** जुलाई 2023 में भारत ने वियतनाम को स्वदेशी मिसाइल कार्वेट **INS कृपाण (INS Kirpan)** उपहार में दिया था। इससे पहले L&T द्वारा बनाई गई 12 हाई-स्पीड गार्ड बोट्स भी दी गई थीं।
- **क्रेडिट लाइन (Line of Credit):** Exim Bank ऑफ इंडिया और वियतनाम के वित्त मंत्रालय के बीच 120 मिलियन और 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नए क्रेडिट समझौतों पर काम चल रहा है।
- **अन्य सहयोग क्षेत्र:** व्यापार, निवेश, कृषि व समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष क्षेत्र, और एयर/पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा हुई।
- **मैत्री वर्ष (Year of Friendship):** दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 55 साल पूरे होने के अवसर पर अगले वर्ष को **'Year of India-Vietnam Friendship'** के रूप में मनाने पर सहमति बनी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

HOUTHIS STRIKE SAUDI ARABIA AGAIN, TARGET MILITARY AIRBASE

Trump claims Iran wants deal as Gulf talks delayed

US President says Tehran wants deal 'quickly and badly'

Reuters
Taiz, Dubai, September 14

A screengrab of a video shows Houthis celebrating territorial gains after an offensive in western Yemen on Monday. REUTERS

YEMEN'S IRAN-aligned Houthis launched a new attack on Saudi Arabia on Monday and Gulf Arab states postponed planned talks with Iran, underscoring fears that the West Asia conflict could spread further and threaten global oil supplies.

US President Donald Trump said Iran wanted to reach a deal with Washington, signalling a possible diplomatic opening despite widening tensions.

"The failing Nation of Iran wants to make a deal, quickly and badly. I will determine whether or not the USA will choose to engage - The concept of which we are open to," Trump wrote on Truth Social.

Trump made the comments after cancellation of the planned Gulf-Iran meeting and as the Houthis expanded military operations beyond Yemen, adding to concerns over the security of energy infrastructure and shipping routes across the region.

The Houthis said they fired dozens of missiles and drones at a military airbase in Khamis Mushait in southern Saudi Arabia, targeting aircraft hangars, radar systems, runways and ammunition depots in retaliation for Saudi airstrikes in Yemen.

Saudi authorities issued emergency alerts there and in three other southern cities which have previously come under Houthi fire. The Houthis have advanced rapidly in Yemen in recent days, capturing territory including Perim Island at the mouth of the Red Sea on Friday.

A separate attack the same day, which Riyadh blamed on Iran-backed fighters in Iraq, knocked out Saudi Arabia's east-west pipeline, a key route that allows Gulf oil exports to bypass the blockaded Strait.

Oman had been due to host a meeting on Monday with Iran and Gulf states to discuss negotiations aimed at reopening Hormuz. But Oman's Foreign Minister Sayyid Badr Albusaidi announced overnight that the meeting had been postponed. Iran said the postponement was at the request of Saudi Arabia.

Iran meanwhile published a list of 77 ships it said had violated its operating protocols in Hormuz and warned they could face fines, detention or confiscation on future transits.

The renewed Yemen conflict poses another challenge for Trump, who faces pressure from Gulf allies to help contain the Houthis but has sought to avoid opening a major new front in the regional war.

The International Organization for Migration estimates 82,000 Yemenis have fled fighting since the start of the month as the Houthis swept into cities, including the historic Red Sea port of Mocha last week.

Trump, who attended a golf tournament at one of his resorts in Ireland, said over the weekend he expected the Iran war to end shortly after November's US midterm elections, after which oil prices would "drop like a rock".

Crown Prince of Saudi, CENTCOM chief discuss Houthi escalation

Dubai: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman discussed regional developments with US Central Command chief Admiral Brad Cooper in Jeddah on Monday, Saudi state media said, amid escalating hostilities with Yemen's Iran-aligned Houthis.

The meeting comes days after three sources familiar with the matter told *Reuters* the crown prince had sought military assistance from US President Donald Trump to help fight the Houthis.

Trump did not agree to US strikes on the group, but Washington told Riyadh it would provide intelligence-sharing and targeting assistance, the sources added. **REUTERS**

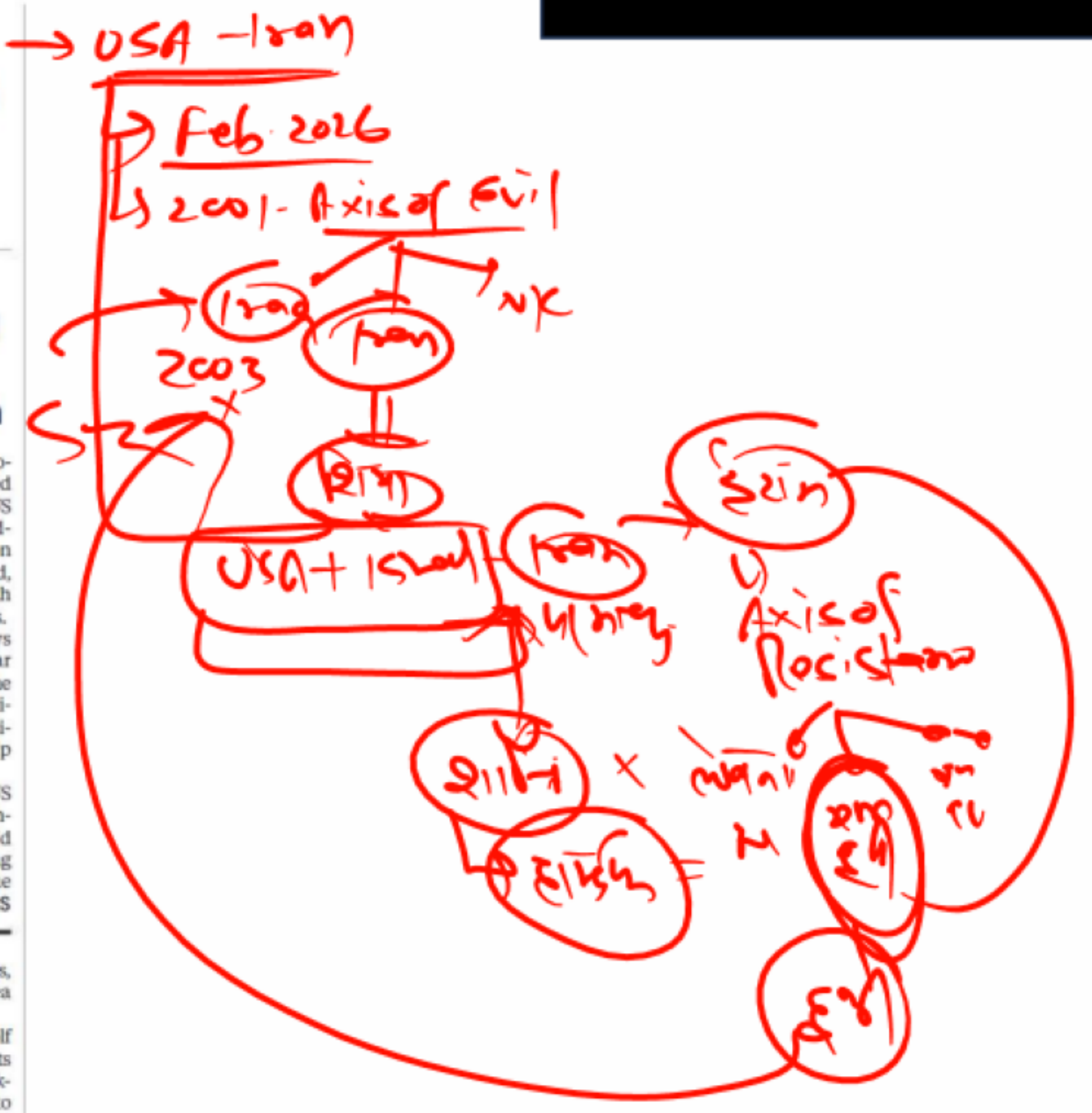

महत्वपूर्ण तथ्य

ROMANIA
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
BULGARIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
GREECE
TÜRKIYE
(TURKEY)
TURKMENISTAN
CYPRUS
SYRIA
LEBANON
IRAQ
IRAN
ISRAEL
PALESTINE
JORDAN
KUWAIT
EGYPT
QATAR
UNITED ARAB EMIRATES
SAUDI ARABIA
OMAN
SUDAN
ERITREA
YEMEN
DJIBOUTI
ETHIOPIA
SOMALIA

महत्वपूर्ण तथ्य

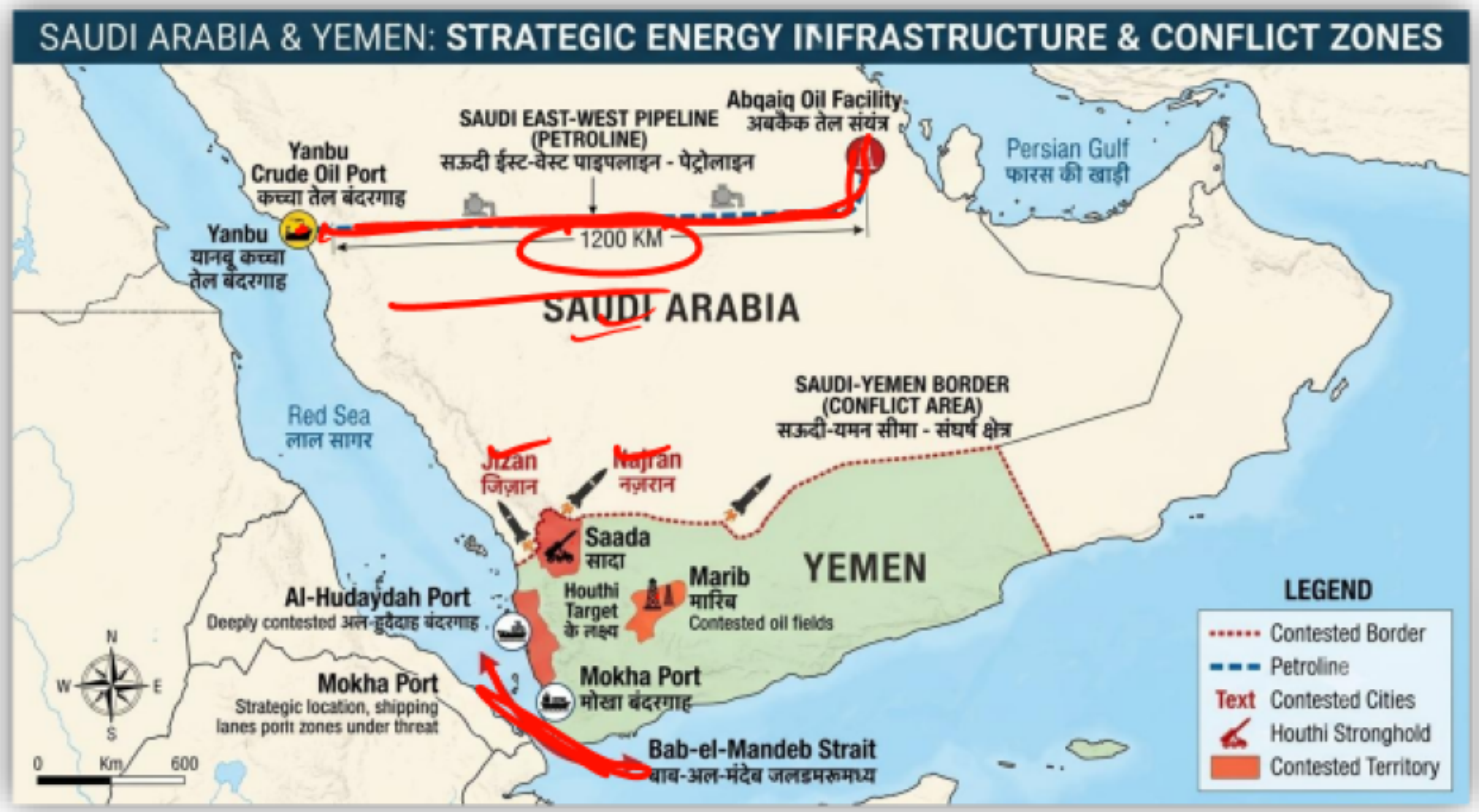

SAUDI ARABIA & YEMEN: STRATEGIC ENERGY INFRASTRUCTURE & CONFLICT ZONES
SAUDI EAST-WEST PIPELINE (PETROLINE)
सऊदी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन - पेट्रोलाइन
Abqaiq Oil Facility
अबक़ैक तेल संयंत्र
Persian Gulf
फारस की खाड़ी
Yanbu Crude Oil Port
कच्चा तेल बंदरगाह
Yanbu
यानबू कच्चा तेल बंदरगाह
1200 KM
SAUDI ARABIA
Red Sea
लाल सागर
SAUDI-YEMEN BORDER (CONFLICT AREA)
सऊदी-यमन सीमा - संघर्ष क्षेत्र
Jizan
जिज़ान
Najran
नज़रान
Saada
सादा
Marib
मारिब
Contested oil fields
YEMEN
Al-Hudaydah Port
Deeply contested अल-हुदैदाह बंदरगाह
Mokha Port
मोखा बंदरगाह
Bab-el-Mandeb Strait
बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य
LEGEND
Contested Border
Petroline
Text Contested Cities
Houthi Stronghold
Contested Territory
0 Km 600

[Abqaiq / अबक़ैक]
फारस की खाड़ी
[Yanbu / यानबू]
सऊदी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन (1200 KM)
सऊदी अरबा
लाल सागर / Red Sea
[जिज़ान / Jizan]
[नज़रान / Najran]
[सादा / Saada] हूथियों का गढ़
यमन
[अल-हुदैदाह बंदरगाह / Al-Hudaydah]
सैन्य संघर्ष क्षेत्र
मोखा बंदरगाह [Mokha Port]
बाब-अल-मंदेब (Bab-el-Mandeb Strait)

महत्वपूर्ण तथ्य

India approves 18-hour power supply to Nepal amid hydropower losses

Pratyush Deep
New Delhi, September 14

THE CENTRE on Monday approved Nepal government's request for early import electricity from India to mitigate a generation shortfall due to the recent disaster. In a statement, the Ministry of Power said it has approved power exports to the Nepal Electricity Authority for 18 hours a day, from midnight to 6 pm, largely covering solar-generation hours, from September 13 to December 31.

Approval has been given for export up to 654 megawatt (MW). Of this, up to 600 MW will be supplied through Muzaffarpur-Dhalkebar 400 kV double-circuit line and up to 54 MW will be transmitted through Tanakpur-Mahendranagar 132 kV single-circuit line, the power ministry said in its statement.

The ministry said the quantum of power to be exported from January 2027, will be reviewed in December, 2026. "The recent floods have caused significant damage to hydropower infrastructure in Nepal, reducing its domestic power generation capacity and creating an additional requirement for electricity. The approval will help Nepal meet its power requirements during this difficult period and further strengthen the close and longstanding energy cooperation between India and Nepal," it added.

The decision to allow electricity exports during solar-generation hours is driven by India's comfortable power availability during the day, mainly due to the expansion of solar capacity in recent years.

Notably, grid operators have had to curtail solar generation during the day as the power system struggles to absorb surplus electricity.

Power will be supplied during solar-generation hours. REUTERS

However, India's power system faces tighter supply conditions during evening and night as solar generation falls. This has become more significant as the country faces an unusual surge in power demand this September, with peak demand approaching levels recorded during the peak summer months. On September 10, peak power demand touched 269 gigawatt (GW), the highest ever recorded for the month.

Data from Grid India show that on September 9, when peak power demand touched 267 GW, the night-time shortfall was around 7.7 GW. On September 10, when peak power demand reached 269 GW, the night-time shortfall was 6.1 GW.

To bridge the evening and night-time shortfall, grid operators have been relying on relatively expensive gas-based power, while coal-fired power plants are also operating at near-maximum levels.

Electricity generation from gas-based power plants rose 80.32% during September 1-9 from the same period last year, an analysis of data from the National Power Portal shows.

Similarly, coal-based generation during the September 1-9 period increased by 25.30%, from 26,135.72 million units (MU) in 2025 to 32,748.96 MU in 2026. Since April, coal-based power generation rose by 10.64%, from 553,730.78 MU in 2025 to 612,663.37 MU in 2026, reflecting heavy reliance on coal to meet the demand during non-solar hours.

The approval for export comes after the Nepal government in August sought advance approvals to import electricity from India from September following the devastating flash floods that hit the country on August 26, *The Indian Express* had reported.

Electricity trade between Nepal and India is seasonal, with Nepal exporting surplus power to the country during monsoon and importing electricity during the dry winter months when domestic hydropower generation declines.

Usually, Nepal makes such requests for electricity imports from India around October. This year, however, the request has come earlier after flash floods damaged the country's power generation capacity.

As per some assessments available with Indian government officials, Nepal's domestic power generation capacity has fallen by around 550 MW after damage to hydropower facilities. As a result, cross-border power flow to India is reduced by nearly 400 MW from previous peak export levels of around 900-1,000 MW. The floods affected 13 hydropower plants, including several under-construction projects, as well as a solar power plant, Nepal's Energy Ministry had said in a statement.

FULL REPORT ON
WWW.INDIANEXPRESS.COM

महत्वपूर्ण तथ्य

- **प्रमुख प्रमुख जलविद्युत परियोजना समझौते (Major Hydropower Project Agreements)**
- हाल के वर्षों में भारत की सार्वजनिक और निजी कंपनियों (जैसे SJVN, NHPC, GMR) ने नेपाल के साथ बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं:

परियोजना का नाम	**क्षमता (Capacity)**	**निष्पादन एजेंसी / कंपनी**	**स्थिति / विवरण**
अरुण-3 (Arun-III)	900 MW	SJVN (भारत सरकार का उपक्रम)	निर्माणाधीन (प्रगति पर), इसका अधिकांश बिजली निर्यात भारत को होगा।
लोअर अरुण (Lower Arun)	669 MW	SJVN	अनुबंध हस्ताक्षरित, अरुण-3 के निचले हिस्से में विकसित किया जा रहा है।
पश्चिम सेती (West Seti)	750 MW	NHPC Limited	नेपाल सरकार और NHPC के बीच विकास हेतु समझौता ज्ञापन (MoU)।
सेती नदी-6 (SR-6)	450 MW	NHPC Limited	पश्चिम सेती के साथ एकीकृत रूप से विकसित की जाने वाली परियोजना।
अपरी करनाल (Upper Karnali)	900 MW	GMR Group (भारत)	परियोजना विकास समझौता (PDA) निष्पादित।
फुकोट करनाल (Phukot Karnali)	480 MW	NHPC और VUCL (नेपाल)	दोनों देशों की सार्वजनिक कंपनियों द्वारा संयुक्त विकास।

महत्वपूर्ण तथ्य

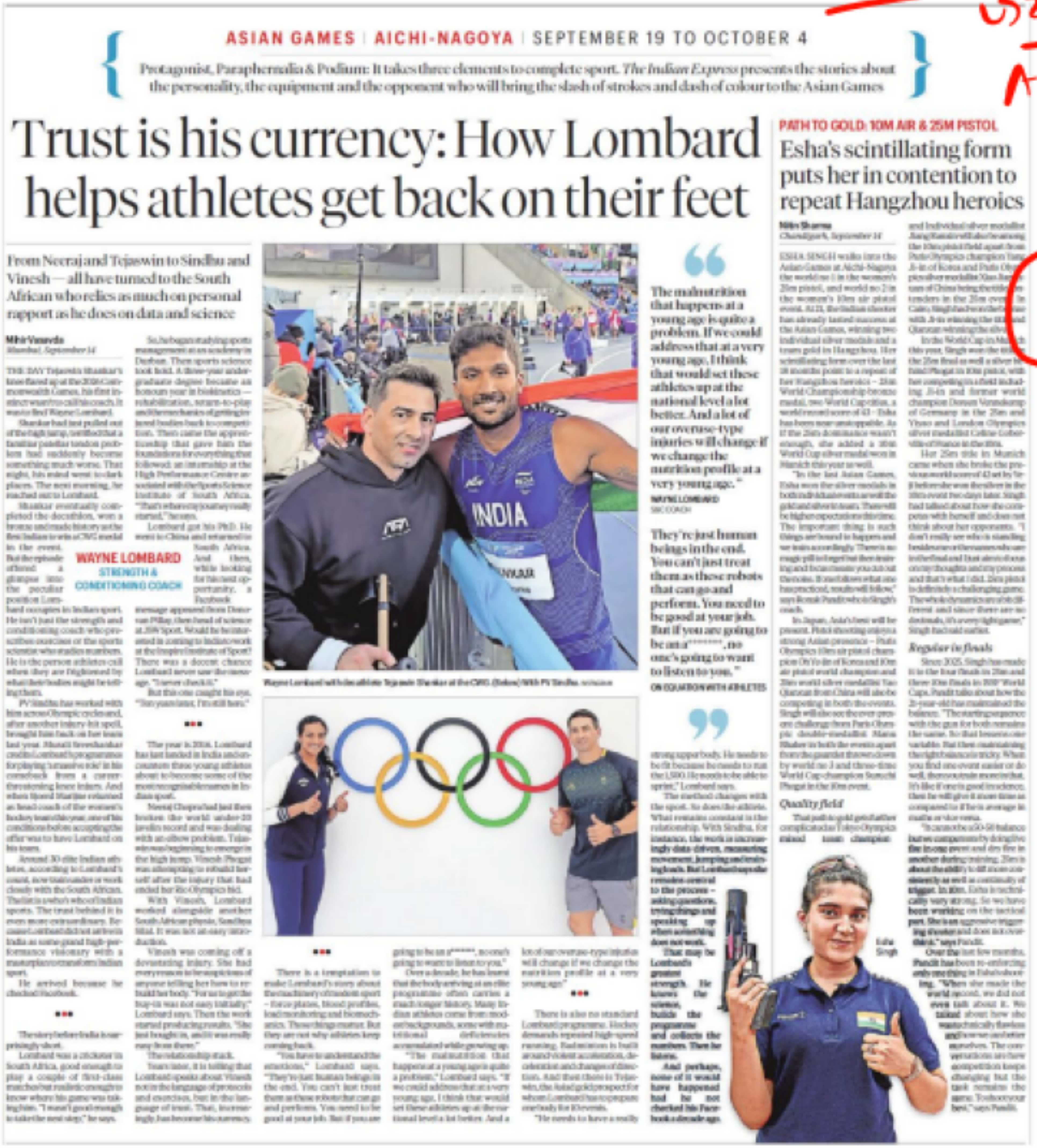
ASIAN GAMES | AICHI-NAGOYA | SEPTEMBER 19 TO OCTOBER 4

Protagonist, Paraphernalia & Podium: It takes three elements to complete sport. *The Indian Express* presents the stories about the personality, the equipment and the opponent who will bring the slash of strokes and dash of colour to the Asian Games

Trust is his currency: How Lombard helps athletes get back on their feet

From Neeraj and Tejaswin to Sindhu and Vinesh — all have turned to the South African who relies as much on personal rapport as he does on data and science

PATH TO GOLD: 10M AIR & 25M PISTOL

Esha's scintillating form puts her in contention to repeat Hangzhou heroics

YouTube Homework

- Common Wealth Games
- US Open
- World Hockey Championship

महत्वपूर्ण तथ्य

ADVERTORIAL | An initiative by RED

NATIONAL ENGINEERS' DAY

From Indus Valley to AI

Engineering Excellence for a Sustainable and Technologically Sovereign India

As India celebrates National Engineers' Day, the nation pays tribute to Sir M. Visvesvaraya and recognises the engineers whose innovation, expertise and vision are helping build a sustainable, resilient and technologically self-reliant India.

From the sophisticated urban planning of the Indus Valley civilisation to today's advances in artificial intelligence, semiconductors and space technology, engineering has been central to India's journey of progress. Engineers have designed the infrastructure that connects communities, developed technologies that transform industries and created solutions to some of society's most complex challenges.

Every year on September 15, India celebrates National Engineers' Day to commemorate the birth anniversary of Bharat Ratna Sir Mokshagundam Visvesvaraya, one of the country's most celebrated engineers and statesmen. His contributions to irrigation, water management, infrastructure and industrial development continue to serve as an enduring example of how engineering can become an instrument of nation-building.

A Legacy of Engineering Excellence

Born on September 15, 1861, in Muddenahalli in present-day Karnataka, Sir M. Visvesvaraya emerged as a pioneering civil engineer whose work extended far beyond the conventional boundaries of his profession. His contributions to irrigation and flood protection, including his association with major water-management projects, demonstrated his belief that engineering should directly improve the lives of people.

As the Diwan of Mysore from 1912 to 1918, he played a significant role in advancing education, industry, infrastructure and economic development. His vision was rooted in the belief that a modern nation required not only physical infrastructure but also knowledge, skills and institutions capable of sustaining long-term growth.

The Government of India instituted Engineers' Day in his honour in 1968. Since then, September 15 has become an occasion to recognise the contribution of engineers across sectors and to inspire young minds to pursue engineering as a means of solving real-world problems.

Engineering India's Growth Story

India's transformation into one of the world's leading economies is closely connected with the work of its engineers. From highways, metro networks and digital infrastructure to renewable energy systems, advanced manufacturing and telecommunications, engineering expertise is enabling the country to operate at an unprecedented scale.

Today, engineers are working at the intersection of multiple disciplines. Artificial intelligence and machine learning are transforming businesses and public services. Robotics and automation are changing manufacturing. Renewable-energy technologies are supporting the transition towards cleaner sources of power. Biomedical engineering is opening new possibilities in healthcare, while advanced materials and semiconductor technologies are becoming increasingly important to India's technological ambitions.

The engineer of today is therefore not merely a designer or builder. Engineers are increasingly problem-solvers, innovators, entrepreneurs and strategic contributors to national development.

The 2026 Theme: Engineering for a Stronger India

The theme for the 59th Engineers' Day in 2026 — "Engineering Excellence for a Sustainable and Technologically Sovereign India" — reflects the changing priorities of the country.

Sustainability and technological sovereignty are becoming critical to India's long-term development. The challenge before engineers is not simply to create new technologies, but to develop solutions that are efficient, inclusive, environmentally responsible and capable of strengthening India's technological independence.

From clean energy and smart infrastructure to artificial intelligence, semiconductor manufacturing, advanced electronics and next-generation mobility, engineers will play a decisive role in shaping India's future.

Technological sovereignty also requires India to strengthen its domestic capabilities in critical technologies. This means investing in research and development, nurturing engineering talent, encouraging innovation and creating stronger connections between universities, research institutions and industry.

Preparing Engineers for the Technologies of Tomorrow

Engineering education is undergoing a significant transformation as emerging technologies reshape the workplace. Traditional engineering disciplines are increasingly intersecting with artificial intelligence, data science, cybersecurity, robotics, biotechnology and advanced manufacturing.

For educational institutions, the challenge is to ensure that engineering graduates are prepared not merely for existing jobs but for opportunities that may emerge in the future. This requires greater emphasis on practical learning, research, interdisciplinary collaboration, innovation and problem-solving.

India's young engineering talent represents one of its greatest strengths. With the right combination of education, industry exposure and research opportunities, this talent can help the country move from being a major consumer of technology to becoming a leading creator of it.

Sir Mokshagundam Visvesvaraya
KCIE, FASC

FACT FILE

19th Diwan of the Mysore Kingdom

In office: 1912-1918

Born: 15 September 1861 Muddenahalli, Chikkaballapura, Kingdom of Mysore (now Karnataka, India)

Died: 14 April 1962 (aged 101) Bangalore, Karnataka, India

Alma Mater:
- Central College, Bangalore
- University of Madras
- College of Engineering, Pune
- University of Bombay

Profession: Engineer

Awards: Bharat Ratna (1955)

His birthday, 15 September, is celebrated as Engineer's Day in India, Sri Lanka and Tanzania in his memory. He was the Chief Engineer of Krishna Raja Sagara dam in the north west suburb of Mysuru city, and also served as one of the Chief Engineers of the flood protection system for the city of Hyderabad.

Building a Sustainable Future

Sustainability is no longer an option; it is an essential component of development. Engineers are at the forefront of designing solutions that can reconcile economic growth with environmental responsibility.

Whether it is developing renewable-energy systems, improving energy efficiency, designing sustainable buildings, managing water resources, reducing industrial waste or creating climate-resilient infrastructure, engineering innovation will be central to addressing the challenges of a rapidly changing world.

The task is particularly significant for India, where the demands of urbanisation, economic growth and a growing population must be balanced with the need to protect natural resources and reduce environmental impact.

From Vision to Nation-Building

Sir M. Visvesvaraya's legacy reminds us that engineering is ultimately about creating lasting value for society. His life demonstrated the importance of discipline, innovation, scientific thinking and an unwavering commitment to national development.

More than a century later, the challenges have changed, but the responsibility remains much the same.

India's engineers are now working on some of the most ambitious projects of the 21st century — from artificial intelligence and semiconductor technology to space exploration, renewable energy, smart cities and advanced healthcare.

As India moves towards the vision of a Viksit Bharat, engineering excellence will remain fundamental to that journey. The engineers of today and tomorrow will not only build bridges, machines and technologies; they will help shape the systems, industries and innovations that define India's place in the world.

RKGIT: Excellence in Engineering Education

Mr. Akshat Goel
Vice Chairman, RKG Group of Institutions

RKGIT, a prominent institution in engineering education, was established in 2000 by the Raj Kumar Goel Educational Foundation. The institute is affiliated with Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow, and approved by the All India Council for Technical Education (AICTE). RKGIT is NAAC accredited with an 'A' Grade and has earned NBA accreditation for its CSE, ECE, IT and B. Pharma programmes, reflecting its commitment to academic quality and outcome-based education.

RKGIT integrates theoretical knowledge with practical exposure to provide students with a comprehensive and industry-oriented engineering education. The institute offers programmes in disciplines including CSE, IT, ECE, EEE, ME, CE, management and pharmacy, with a strong focus on experiential learning. Modern laboratories, project-based learning, experienced faculty and opportunities for practical exposure enable students to translate classroom knowledge into real-world applications.

RKGIT has entered into an academic collaboration with IIT Mandi to offer a Minor Degree Programme in Artificial Intelligence. RKGIT has been conferred with the prestigious Diamond Rating by "QS I-GAUGE" in recognition of its academic excellence and institutional achievements. As part of its commitment to strengthening technology-driven learning, the institute is set to establish an Apple iOS Development Centre.

Shri Dinesh Kumar Goel, Chairman, Raj Kumar Goel Group of Institutions, believes that engineers must be equipped to address complex societal challenges through innovation, sustainability, ethical decision-making and social responsibility.

Echoing this vision, I also highlight the importance of continuous learning in today's rapidly changing technological environment. I encourage students to embrace critical thinking, creativity and practical problem-solving so that they can confidently respond to emerging technologies and changing industry requirements.

Inspired by Sir M. Visvesvaraya's philosophy of excellence and service, RKGIT empowers young minds to innovate, solve real-world challenges and contribute to nation-building.

महत्वपूर्ण तथ्य

- **Engineers' Day** भारत में महान सिविल इंजीनियर और भारत रत्न **सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (Sir M. Visvesvaraya)** की जयंती के अवसर पर हर साल **15 सितंबर** को मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु

- **इतिहास और शुरुआत:**
  - भारत सरकार ने वर्ष 1968 में सर एम. विश्वेश्वरैया के योगदान को सम्मानित करने के लिए 15 सितंबर को 'इंजीनियर्स डे' घोषित किया था।
- **सर एम. विश्वेश्वरैया कौन थे?**
  - **जन्म:** 15 सितंबर 1861 (कर्नाटक के मुद्देनहल्ली में)।
  - **सम्मान:** उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **'भारत रत्न'** से सम्मानित किया गया था।
  - **मैसूर के दीवान:** वे 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान भी रहे।
- **प्रमुख योगदान (Major Contributions):**
  - **कृष्णराज सागर बांध (KRS Dam):** मैसूर में इस ऐतिहासिक बांध का निर्माण उन्हीं की देखरेख में हुआ था, जो उस समय एशिया के सबसे बड़े जलाशयों में से एक था।
  - **ऑटोमैटिक स्लुइस गेट्स (Automatic Sluice Gates):** उन्होंने पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित फ्लडगेट्स का पेटेंट कराया, जिसे पुणे के खड़कवासला जलाशय में पहली बार लगाया गया था।
  - **ब्लॉक सिस्टम (Block System):** सिंचाई प्रणाली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए उन्होंने 'ब्लॉक सिस्टम' विकसित किया।
  - **संस्थागत योगदान:** उन्होंने बेंगलुरु में 'यूवीसीई' (UVCE) इंजीनियरिंग कॉलेज और मैसूर बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Engineers' Day**
- भारत के अलावा दुनिया के अन्य देश भी अलग-अलग तारीखों पर यह दिवस मनाते हैं:
- **श्रीलंका और तंजानिया:** भारत की तरह ये देश भी 15 सितंबर को ही सर एम. विश्वेश्वरैया की याद में Engineers' Day मनाते हैं।
- **विश्व इंजीनियरिंग दिवस (World Engineering Day):** यूनेस्को (UNESCO) द्वारा हर साल **4 मार्च** को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

गृह मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

हिन्दी दिवस 2026 पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का संदेश

14 september

प्रविष्टि तिथि: 14 SEP 2026 10:16AM by PIB Delhi

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएँ!

हमारा देश भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि की अनुपम भूमि है। सब लोग कहते है कि हमारी भाषाएं अलग-अलग हैं वो हमारी कमी है, मगर मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इतनी सारी भाषाएं होना है। अपने साथ हर भाषा एक इतिहास, लोकपरंपरा और जीवन-दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। यही भाषाई बहुलता भारत की 'विविधता में एकता' की भावना को सशक्त बनाती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती। वह किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है।

हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है, जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी उन्होंने 'सत्यार्थ प्रकाश' हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्लाभाषी थे, पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सम्पर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को 'जय हिंद' का नारा दिया। यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन-संवाद की भाषा बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी।

मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूँ, तो जो भाषा मुझे वहाँ के सामान्यजन से सीधे जोड़ती है, वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए, तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, 'पृथ्वीराज रासो' की वीरगाथाएँ, फिर भक्तिकाल का वह अद्भुत युग - जब तुलसीदास जी ने रामकथा को घर-घर पहुँचाया और सूरदास जी ने वात्सल्य को स्वर दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **हिंदी दिवस (14 सितंबर)** भारत में हिंदी भाषा के सम्मान, प्रचार-प्रसार और इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है।

इतिहास और पृष्ठभूमि

- **संवैधानिक दर्जा (14 सितंबर 1949):** 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा (Constitutional Assembly) ने लंबी चर्चा के बाद हिंदी (देवनागरी लिपि में) को भारत संघ की **आधिकारिक भाषा (Official Language)** के रूप में स्वीकार किया था।
- **अनुच्छेद 343(1):** भारतीय संविधान के भाग 17 के **अनुच्छेद 343(1)** में यह प्रावधान है कि "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।"
- **पहला हिंदी दिवस (1953):** राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर भारत सरकार ने 1953 से हर साल 14 सितंबर को आधिकारिक रूप से 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया।
- **व्योहार राजेंद्र सिंह की भूमिका:** 14 सितंबर को हिंदी के मूर्धन्य विद्वान **व्योहार राजेंद्र सिंह** का 50वां जन्मदिन भी था, जिन्होंने काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों के साथ मिलकर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

आयुष

Azadi Ka Amrit Mahotsav

परंपरा, प्रमाण और वैश्विक स्वास्थ्य तक आयुर्वेद

बढ़ती आयुष अर्थव्यवस्था, घरेलू स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता, चिकित्सा मूल्य यात्रा और अनुसंधान आयुर्वेद के वैश्विक विस्तार के नए अवसर खोल रहे हैं

प्रविष्टि तिथि: 14 SEP 2026 5:34PM by PIB Delhi

आयुर्वेद वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चाओं में हाशिए से निकलकर अब मुख्यधारा की ओर बढ़ रहा है। भारत की विस्तारित आयुष अर्थव्यवस्था, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के घरेलू स्तर पर बढ़ते उपयोग तथा वेलनेस और चिकित्सा मूल्य यात्रा में बढ़ती रुचि आयुर्वेद के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। इसी के साथ वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय भी पारंपरिक चिकित्सा, अनुसंधान और प्रमाणों पर अधिक जोर दे रहा है।

भारत में 23 सितम्बर, 2026 को 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे समय में यह अवसर विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष की थीम "स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद" है। यह ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत अपनी सदियों पुरानी ज्ञान प्रणाली को आधुनिक अनुसंधान, गुणवत्ता मानकों और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ढांचों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब चुनौती केवल आयुर्वेद को दुनिया तक पहुंचाने की नहीं है, बल्कि ऐसे प्रमाण, विश्वसनीयता और संस्थागत आधार तैयार करने की है, जो इसके जिम्मेदार वैश्विक विस्तार को समर्थन दे सकें।

पिछले एक दशक में आयुष क्षेत्र ने उल्लेखनीय आर्थिक विस्तार देखा है, जिससे आयुर्वेद के विकास और व्यापक स्वीकार्यता के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। आयुष बाजार वर्ष 2014 में 2.85 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023 में 43.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि इसी अवधि में आयुष निर्यात 1.09 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2.16 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। सरकार की पहलों में एमएसएमई और स्टार्टअप को सशक्त बनाने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में उद्यमिता, नवाचार और निवेश के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिली है।

आयुष पद्धतियों की घरेलू स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता इस विस्तार के लिए एक और महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान आयुष पर किए गए पहले विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण में 1,81,298 परिवारों को शामिल किया गया, जिनमें 1,04,195 ग्रामीण और 77,103 शहरी परिवार थे। सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में 94.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 96 प्रतिशत आयुष जागरूकता दर्ज की गई। इसमें यह भी पाया गया कि पिछले 365 दिनों के दौरान 46.3 प्रतिशत ग्रामीण निवासियों और 52.9 प्रतिशत शहरी निवासियों ने उपचार या रोकथाम के लिए आयुष का उपयोग किया था। उपचार के लिए आयुर्वेद सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली आयुष पद्धति के रूप में उभरा, जो इसके मजबूत घरेलू आधार तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल और वेलनेस में इसके योगदान की संभावनाओं को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

रक्षा मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय वायु सेना ड्रोनाथॉन – 2026

प्रविष्टि तिथि: 14 SEP 2026 8:01PM by PIB Delhi

वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले भारतीय वायु सेना ड्रोनाथॉन-2026 का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्रालय एवं एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 'ड्रोनाथॉन-2026' भारतीय वायु सेना की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की बिना पायलट वाली हवाई प्रणालियों के उद्योग से सीधे जुड़ना और वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में उभरती नई तकनीकों का परीक्षण करना है। 14 से 16 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारत के तेजी से विकसित हो रहे बिना पायलट वाली हवाई प्रणालियों के पारिस्थितिकी तंत्र से 20 से अधिक प्रमुख रक्षा कंपनियां, स्टार्ट-अप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवोन्मेषक भाग ले रहे हैं।

भारतीय वायु सेना मानव-संचालित विमानन के लिए मानवरहित प्रणालियों को एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में देखती है। ये प्रणालियां कमांडरों को हवाई अभियानों की पहुंच, निरंतरता, कार्रवाई क्षमता और परिचालन लचीलेपन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराती हैं। इस ड्रोनाथॉन के दौरान भाग लेने वाली कंपनियां और नवोन्मेषक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) व उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे।

इन प्रदर्शनों में कई तरह की परिचालन क्षमताएं दर्शाई जाएंगी, जिनमें निगरानी और टोह लेने, स्वायत्त संचालन, स्वार्म टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तथा मानवरहित विमान-रोधी प्रणालियों (सीयूएएस) जैसी विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ड्रोनाथॉन-2026 का मुख्य उद्देश्य केवल तकनीक का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि उसे वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में प्रभावी साबित करना है। इसके तहत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इन प्रणालियों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही, यह भी परखा जा रहा है कि ये प्रणालियां बदलती परिचालन आवश्यकताओं और उभरते खतरों के अनुरूप खुद को कितनी प्रभावी ढंग से ढाल सकती हैं।

Overview

- Data Center
- UCC
- Anthropic CEO Open Latter
- CPI, WPI
- MDR on UPI
- India-Vietnam
- USA-IRAN Conflict
- Saudi Arab - Houthis Conflict
- India Approves Hydro Power to Nepal
- Asian Games
- Engineers day
- Ayurved Day
- Dronathon

Thank You

Result Mitra

Thanks For Watching

Learn Share Grow Together ♡

Better Students Brighter Tomorrow

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Result Mitra

Subscribe Now

DISCIPLINE

CONSISTENCY

SUCCESS

Stay Connected

Small Steps Big Results